भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3336
12.07.2019 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3336. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार में गत दो वर्षों के दौरान भारत में कृषि सहित विभिन्न पारिस्थितिकियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ सहयोग करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कार्य-योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): वर्ष 2011-17 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना के तहत पूरे देश में फसल पैदावार पर परिवर्तनीय मौसम के उतार-चढ़ाव के संभावित प्रभाव पर अध्ययन किया गया। महत्वपूर्ण स्थानिक-अल्पकालिक भिन्नताओं सहित शताब्दी के अंत तक गेहूँ की पैदावार में 6 से 12 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गई है। वर्षा में परिवर्तन और वर्षा आधारित चावल की उपज का विश्लेषण सितंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान अधिकतम परिवर्तन सहित मासिक वर्षा के साथ चावल की पैदावार का घनिष्ट सहसंबंध दर्शाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय-गांगेय क्षेत्र के लिए फसल अनुकरण मॉड्यूलों के माध्यम से चावल, गेहूँ और गन्ने पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता की है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों (आईसीआरआईएसएटी), हैदराबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से चने और अरहर की फसल में लगी बीमारियों और कीट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय तटीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से होने वाली विषम घटनाओं की जांच करने और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय अवसंरचना और जल संसाधनों की संवेदनशीलता के मूल्यांकन का अध्ययन करवाने में सहायता भी कर रहा है।

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से सात नदी बेसिनों नामत: महानदी, माही, लूनी,तापी, साबरमती, सुबर्नरेखा और ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली नदियों पर जल मौसम विज्ञानीय प्रक्रियाओं के संबंध में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय की "जलवायु परिवर्तन और भारत : एक 4X4 आकलन- 2030 दशक के लिए एक खण्डीय और क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक से एक रिपोर्ट में भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों नामत: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर

भारतीय अर्थव्यवस्था के चार मुख्य क्षेत्रों नामत: कृषि, जल, वन और मानव स्वास्थ्य पर 2030 में पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) और (घ) : जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है और इसके लिए सभी देशों का 'साझा किंतु विभिन्न उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांत के आधार पर सहयोग अपेक्षित है। भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यढांचा कन्वेंशन, उसके क्योटो प्रोटोकॉल तथा पेरिस समझौते का एक पक्षकार है। भारत उपर्युक्त मंचों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली, हरित भारत, वहनीय कृषि एवं जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्यनीतिक जानकारी के क्षेत्रों में आठ मिशनों संबंधी कार्रवाईयों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तैंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना तैयार की गई हैं। एनआईसीआरए परियोजना के तहत, संवहनीय कृषि राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में ताप तथा सूखा सहिष्णु गेहूँ, बाढ़ सहिष्णु चावल, सूखा सहिष्णु दालें,जल भराव तथा उच्च तापमान सहिष्णु टमाटर की किस्मों को विकसित किया गया है । आईसीएआर ने अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भारतीय अर्द्धशुष्क उष्ण कटिबंधों में मूँगफली तथा अरहर पर ध्यान देते हुए जल संभर क्षेत्रों में जलवायु विभिन्नता और परिवर्तन में अनुकूलन बढ़ाने के लिए एक परियोजना पर काम किया है। एनआईसीआरए का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संघटक किसानों की लचीली और अनुकूली क्षमता को बढ़ाता है तथा देश के 151 जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में जलवायु भिन्नताओं का समाधान करता है।

*****